



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, २६ अगस्त, १९९६/४ भाद्रपद, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खंड)

अधिसूचना

शिमला-२, २७ मई, १९९६

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी(१६)-१/९६.—हिमाचल प्रदेश गेड्यूल्ड, कास्टम ऐण्ड गेड्यूल्ड ट्राइवज डिवेलपमेन्ट कारपोरेशन ऐक्ट, १९७९ (१९७९ का २) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश

के राज्यपाल के तारीख 14-5-95 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि)।

# हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979

(1979 का 20)

(30-4-96 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तीसरे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

## अध्याय-1

### प्रारम्भिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 है ।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो:--

परिभाषाएं ।

(क) "कृषि विकास" के अन्तर्गत बागवानी, वन, दुग्ध उद्योग, मूर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन और पशु-प्रजनन, मत्स्य पालन तथा रेशम उत्पादन का विकास है :--

(कक) "बैंक" से अभिप्रेत है,--

1949 का 10

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी;

1955 का 23

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

1959 का 38

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ;

1976 का 21

(iv) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ;

1970 का 5

(v) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक ;

1949 का 10

(vi) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बैंककारी संस्था;

1963 का 1

(vii) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित कृषिक पुनर्वित्त एवं विकास निगम ;

- (viii) हिमाचल प्रदेश कृषि उधार संक्रिया और प्रकीर्ण उपबन्ध बैंक अधिनियम, 1973 का 7 1972 की धारा 2 के खण्ड (ग) में परिभाषित कृषि उद्योग निगम;
- (ix) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कृषि वित्त निगम 1956 का 1 लिमिटेड ; और
- (x) राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बक के रूप में, राजपत्र में अधिसूचित, कोई अन्य वित्तीय संस्था ;
- (ग) "बोर्ड" से निगम का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ग) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
- (घ) "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" से निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (घ) "कलक्टर" से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कलक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कोई अन्य अधिकारी जो सहायक कलक्टर वर्ग-1 की पंक्ति से नीचे का न हो, इसके अन्तर्गत है ;
- (ङ) "निगम" से धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति विकास निगम अभिप्रेत है ;
- (च) "निदेशक" से बोर्ड का निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं ;
- (छ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (ज) "उद्धार-प्रतिभूति-अन्तर धन" से वह उद्धार प्रतिभूति-अन्तर धन अभिप्रेत है जो वित्तीय बैंककारी संस्थाओं द्वारा हितग्राहियों से अपेक्षित हो ;
- (झ) "विपणन" से कृषि अथवा औद्योगिक उत्पाद के, चाहे वे प्रारम्भिक रूप में हों या अर्ध-संसाधित अवस्था में हों, यातायात, श्रेणीकरण, एकत्रीकरण, विपणन और बिक्री से सम्बन्धित सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं ;
- (ञ) "विहित" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ट) "प्रसंस्करण" से कृषि उपज के प्रसंस्करण से सम्बन्धित वे सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं जिनसे यह विपणन या उपभोग के लिए उपयुक्त बन जाएं और कच्चे माल की खरीद तथा भण्डारकरण, उपस्कर की खरीद और प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित मशीनरी की खरीद, प्रतिष्ठापन और परिचालन और तैयार उत्पाद का भण्डारकरण भी इसके अन्तर्गत है ;
- (टट) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग अथवा समूह अभिप्रेत हैं जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति समझा गया है ;

1932 का 9

1860 का 2

1969 का 3

(ड) "अनुसूचित जाति संगठन" या "अनुसूचित जनजाति संगठन" से अभिप्रेत है, भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म या सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगम या हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसायटी जिस में समादत पूंजी का 51 प्रतिशत से अत्युन, यथास्थिति, अनुसूचित जाति के सदस्यों या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा धारित है ;

(डड) "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में इस का है ;

(ड) "लघु उद्योग" से ऐसा कुटीर और लघु उद्योग अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ण) "पूति तथा भण्डारकरण" से कृषि सामग्री की पूति और भण्डारकरण तथा भण्डारों, शीतगारों और भण्डारगारों की स्थापना, अनुरक्षण और परिचालन अभिप्रेत है ।

## अध्याय-2

### हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम का निगमन और इसकी पूंजी

3. (1) राज्य सरकार, उस तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम नामक निगम की स्थापना कर सकेगी ।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति अर्जित करने, उसे धारण करने का और उसका व्ययन करने तथा मविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद लः सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

4. (1) निगम का मुख्य कार्यालय शिमला में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) निगम राज्य में या इसके बाहर ऐसे स्थानों पर, जो वह उचित समझे अपने कार्यालय या एजेंसियां स्थापित कर सकेगा ।

5. (1) निगम की प्राधिकृत पूंजी बीस करोड़ रुपये से अनधिक ऐसी राशि होगी, जो राज्य सरकार नियत करे :

परन्तु जहां नियत आरम्भिक पूंजी बीस करोड़ रुपये से कम है, वहां राज्य सरकार

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना ।

निगम का मुख्यालय

निगम की पूंजी ।

समय-समय पर पूंजी को ब्रोस करोड़ रुपये से अनधिक ऐसी राशि तक बढ़ा सकेगी जो वह उचित समझे ।

(2) ऐसी पूंजी का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “प्राधिकृत पूंजी” के अन्तर्गत प्रबन्धकीय सहायता के लिए निगम द्वारा प्राप्त अनुदान-सहायता नहीं होगी ।

### अध्याय-3

#### निगम का प्रबन्ध

प्रबन्ध ।

6. (1) निगम के मामलों और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबन्ध, निदेशक बोर्ड में निहित होगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा प्रयोग में लाई जा सकेंगी या की जा सकेंगी ।

(2) निदेशक बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय लोकहित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और निगम की (ऋणों की) शोधन क्षमता को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा और नीति के प्रश्न पर इसका मार्ग दर्शन ऐसे अनुदेशों द्वारा किया जाएगा जो इसे राज्य सरकार द्वारा दिये जाएं ।

(3) यदि कोई ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो, उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

निदेशक बोर्ड ।

7. (1) बोर्ड का गठन सोलह निदेशकों से होगा जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे :

परन्तु राज्य सरकार के कल्याण विभाग में सेवारत अधिकारियों में से कम से कम दो निदेशक नाम निर्देशित किए जाएंगे और शेष उन व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किए जायेंगे जिनको उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन, कृषि, कृषि-उद्योग, जल विकास परियोजनाओं, वित्त, सहकारी और वित्तीय संस्थाओं का विशेष ज्ञान हो :

परन्तु यह और कि कम से कम दो गैर-सरकारी निदेशक, अनुसूचित जाति के और एक गैर-सरकारी निदेशक अनुसूचित जनजाति, का होगा ।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से किसी को निगम का अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष नामनिर्देशित करेगी ।

(3) मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्यथा के कारण होने वाली अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या निदेशक के पद में रिक्ति यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में उपरिस्थित रीति में भरी जाएगी ।

(4) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो बोर्ड द्वारा इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन उन्हें सौंपे जाएं या प्रदत्त की जाएं ।

(5) इस अधिनियम के उपाबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और उन्हें देय फीस और भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य निदेशक राज्य सरकार के प्रसाद पद धारण पदावधि करेंगे ।

9. कोई व्यक्ति निगम का निदेशक नामनिर्देशित किए जाने या होने के लिए निरहित होगा— निदेशक के पद की निरर्हता ।

(क) यदि वह दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या उसने अपने ऋणों का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ प्रशमित किया है;

(ख) यदि वह विकृत-चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध है या किया गया है जो राज्य सरकार के विचार में नैतिक अधमता से अन्तर्गस्त है ; या

(घ) यदि उसे किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित निगम की सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है ।

10. यदि कोई निदेशक, बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई आर्थिक हित रखता हो तो वह प्रासंगिक परिस्थितियों की जानकारी के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति प्रकट करेगा और प्रकटीकरण को, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के विवरण में अभिलिखित किया जाएगा, और निदेशक उस विषय के बारे में बोर्ड या समिति के किसी विचार विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा । कतिपय मामलों में निदेशक का भाग न लेना ।

11. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या निदेशक राज्य सरकार को इसकी लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है । त्यागपत्र ।

12. (1) बोर्ड की बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी और बैठकों में कारबार (बैठक में गणपूर्ति सहित) के संयोजन के बारे में ऐसे नियमों या प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा जो विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाए । बैठकें ।

(2) अध्यक्ष की उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में निदेशकों द्वारा अपने में से चुना गया बोर्ड का कोई अन्य निदेशक बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले निदेशकों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह इसका प्रयोग करेगा।

प्रबन्ध निदेशक । 13. राज्य सरकार निदेशकों में से एक को, जो राज्य सरकार का अधिकारी हो, प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करेगी जो इसके प्रसादपर्यन्त उस पद को धारण करेगा।

## (2) प्रबन्ध निदेशक—

- (क) इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा;
- (ख) निगम के कार्यचालन प्रबन्ध और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो बोर्ड विनियमों द्वारा या अन्यथा उसे सौंपे;
- (घ) ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों से शासित होगा जो बोर्ड द्वारा अवधारित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।

(3) यदि प्रबन्ध निदेशक अंग-शैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है या अवकाश पर अथवा अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थिति है जिससे उसकी नियुक्ति की रिक्ति नहीं होती है तो, राज्य सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

नियुक्ति में त्रुटि से कार्य, आदि का अविधिमान्य न होना । 14. (1) बोर्ड या इसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल, यथास्थिति, बोर्ड या समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रयुक्त या अविधिमान्य नहीं होगी।

(2) निदेशक या किसी समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य केवल इन आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि वह निदेशक होने या सदस्य होने के लिए निरहित था या उसके नामनिर्देशन में कोई अन्य त्रुटि थी।

निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारी । 15. (1) बोर्ड, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह निगम के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे और विनियमों द्वारा या अन्यथा, उनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा उन्हें देय पारिश्रमिक अवधारित कर सकेगा।

(2) बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन



अगली ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) बोर्ड, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग और अन्तोदय परिवारों के सदस्यों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के बारे में निगम के अधीन सेवा में ऐसे सदस्यों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

#### अध्याय—4

#### निगम के कृत्य और निधियाँ

16. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आर्थिक उत्थान के कार्य का जिम्मा लेना निगम का प्राथमिक कर्तव्य होगा।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित की शक्ति भी है:—

(i) सरकार द्वारा इस निमित्त यथा अनुमोदित कृषि विकास कार्यक्रमों, पशुपालन, विपणन, प्रसंस्करण, कृषि-उपज की पूर्ति और भण्डारकरण, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, और ऐसे अन्य व्यापार, कारोबार या क्रियाकलापों की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को बेहतर जीविका अर्जित करने में समर्थ बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सहायक हो, योजना बनाना, अभिवृद्धि करना, जिम्मा लेना, और महायत्ना करना;

(ii) नियोजनाकूल उद्योगों, कुटीर और लघु उद्योगों आदि की स्थापना करने के कार्यक्रमों का, तकनीकी जानकारी, प्रबन्धकीय सहायता, वित्तीय सहायता और किसी अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था करके जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित हो, जिम्मा लेना;

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संगठनों को ऋण देकर या ऊपर निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए उद्धार प्रतिभूति अन्तस्थान के प्रति सीधे या ऐसे अभिकरण, संगठन अथवा संस्था के माध्यम से जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हों ऋण देकर वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना;

(iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संगठनों द्वारा किसी वित्तीय/बैंककारी संस्था से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति देना;

(v) जब कभी भी ऐसा करना अपेक्षित हो तो, कृषि या अन्य उपज अथवा अन्य माल के उगापन, पूर्ति और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

- (vi) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के नियोजन की व्यवस्था करने के प्रयोजन से ऐसे उद्योगों और कारबार की अभिवृद्धि की दृष्टि से, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों तथा लघु कारबार से सम्बन्धित समस्याओं, ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योगों की संभाव्यता और उनके विकास के क्षेत्र के अवधारण के लिए सर्वेक्षण, अनुसंधान या अध्ययन की सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (vii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संगठनों द्वारा लघु उद्योगों की संभाव्यता निर्मित परिसाधित उत्पादों और उद्योगों में प्रचार और विपणन की व्यवस्था करना ;
- (viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संगठनों को राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था की ओर से अनुदान तथा आर्थिक सहायता देना ;
- (ix) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, धन उधार लेना;
- (x) उपहार, अनुदान और दान प्राप्त करना;
- (xi) ऋणपत्र और ऋण-पत्र जारी करना;
- (xii) वचन-पत्र, विनिमय बिल, हुंडी, बिल, अधिपत्र, ऋणपत्र और अन्य परक्राम्य लिखते लिखना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, छूट देना, निष्पादन करना और जारी करना ;
- (xiii) निगम की अधिगेष निधि का सरकारी प्रतिभूति में या ऐसी अन्य रीति से जैसे बोर्ड निश्चित करे, निवेश और जमा करना;
- (xiv) मंविदा करना; और
- (xv) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन जो विहित किए जाएं या जो इस अधिनियम के अधीन इसे प्रदत्त कृत्यों में से किसी के अनुपूरक या आनुषंगिक अथवा पारिणामिक हैं ।

निगम को 16-क. (1) राज्यपाल, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निगम से परामर्श के पश्चात्, निगम या इसके अधिकारियों को राज्य में समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक बीमा अथवा उत्थान के सम्बन्ध में शर्त सहित या शर्त रहित अनिवार्य कार्य सौंप सकेगा ।

जाना ।

(2) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा और निगम से परामर्श के पश्चात् निगम को, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त अभिकरणों, प्राधिकरणों या अधिकाधिकारियों पर, पर्यवेक्षण स्वरूप की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा, जो राज्य में समाज के

कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक बीमा और उत्थान की, व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हों।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निगम को कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदत्त किए जाएं तो, निगम वैसी ही शक्तियों का प्रयोग, वैसे ही कर्तव्यों का निर्वहन और वैसे ही कृत्यों का अनुपालन करेगा जैसे धारा 16 के अधीन इसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के अनुपालन के लिए करता और इस अधिनियम के उपबन्ध, तदनुसार लागू होंगे।

(4) जहां इस धारा के फलस्वरूप निगम या इसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य प्रदत्त या अधिरोपित किए गए हैं वहां जो उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में निगम द्वारा उपरगत किसी अनिरीकृत प्रशासनिक लागत की बाबत राज्य सरकार द्वारा निगम को ऐसी राशि मंदत्त की जाएगी, जो करार पाई जाए।

17. निगम सात पृथक् निधियां स्थापित करेगा और रखेगा, अर्थात् :—

- (क) विकास और वित्त निधि ;
- (ख) प्रत्याभूति निधि ;
- (ग) डूबंत ऋण निधि ;
- (घ) राहत और सामूहिक हित निधि ;
- (ङ) सहायता अनुदान और सहायकी निधि ;
- (च) ऋण निधि ; और
- (छ) अतिरिक्त कृत्य निधि ।

निगम द्वारा  
सात निधियां  
रखना ।

18. धारा 19, 20, 21, 22, 23 और 23-क में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय—

- (1) विकास और वित्त निधि में वे सभी रकमें जो निगम द्वारा भी किसी स्त्रांत से, जो भी हो, प्राप्त की जाएं, जमा की जाएंगी।
- (2) निगम द्वारा खर्च की गई सभी रकमें इस निधि में विकलित की जाएंगी।

भूमि विकास  
और वित्त  
निधि ।

19. (1) प्रत्याभूति निधि में प्रत्येक वर्ष ऐसी राशि जमा की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए निगम के व्ययन पर रखी जाएगी और ऐसी राशि पर समय-समय पर प्रोद्भूत व्याज भी प्रत्येक वर्ष इस निधि में जोड़ा जाएगा।

प्रत्याभूति  
निधि ।

(2) निगम भी अपने शुद्ध लाभ के ऐसे भाग का इस निधि में अभिदाय कर सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

20. डूबंत ऋण निधि में प्रत्येक वर्ष —

- (क) निगम द्वारा अपने शुद्ध लाभ का दस प्रतिशत ; और
- (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में ऐसी राशि जो खण्ड (क) के अधीन जमा राशि के समतुल्य हो ; जमा की जाएगी ;

डूबंत ऋण  
निधि ।

परन्तु इसकी कोई भी बात, राज्य सरकार को इस निधि में जमा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में ऐसी राशि देने से, जो यह उचित समझे, विवर्जित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

राहत और सामूहिक 21. राहत और सामूहिक हित निधि में प्रतिवर्ष, निगम के शुद्ध लाभ के साठे  
सामूहिक आठ प्रतिशत से अनधिक, ऐसी रकम जमा की जाएगी जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की  
हित निधि। जाए।

महायता अनुदान। 22. सहायता अनुदान या सहायकी के रूप में निगम द्वारा किसी भी स्त्रोत से प्राप्त  
अनुदान। सभी रकमों इस निधि में जमा की जाएंगी और निगम द्वारा यह उन प्रयोजनों के लिए  
और सहायकी प्रयोग की जाएगी जिनके लिए, यथास्थिति, सहायता अनुदान या सहायकी प्रदान की  
निधि। गई है।

ऋण निधि। 23. निगम द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्था स्त्रोतों से अभिप्राप्त सभी ऋण इस निधि  
में जमा किए जाएंगे और उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाएंगे जिस के लिए ऐसे  
ऋण अभिप्राप्त किए गए हैं।

अतिरिक्त कृत निधि। 23-क. निगम द्वारा, राज्य सरकार या अन्य किसी स्त्रोत से धारा 16-क के  
अधीन इस सीपे गए अतिरिक्त कृत्यों के अनुपालन के लिए प्राप्त सभी रकमों इस अनधि  
में जमा की जाएंगी और निगम द्वारा इसका प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा  
जिम के लिए ऐसी रकम का प्रावधान किया गया है।

#### अध्याय—5

#### ऋण

ऋणों के लिए शर्तें अधिरोपित करने की शक्ति। 24. कोई ऋण देते समय या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्धार-प्रतिभूति अन्तरधन  
को व्यवस्था करते समय निगम, ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी यह निगम के  
हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक या समीचीन समझे :

परन्तु ऐसे ऋणों, उद्धार प्रतिभूति अन्तरधन पर प्रभावं व्याज की दर निगम द्वारा,  
समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से, नियत की जाएगी।

करार पाई गई अधि से पूर्व प्रति-संदाए मांगने की शक्ति। 25. किसी करार में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी निगम, लिखित सूचना  
द्वारा, किसी ऋणी से निगम को तत्काल अपना पूरा ऋण चुकाने की अपेक्षा कर  
सकेगा—

(क) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि ऋण उद्धार प्रतिभूति अन्तरधन के  
लिए आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की मिथ्या या भ्रामक सूचना अथवा  
विवरण दिया गया था ;

(ख) यदि ऋणी निगम के साथ किए गए किसी प्रकार के किन्हीं निबन्धनों का  
अनुपालन करने में असफल रहा हो ;

(ग) यदि युक्तियुक्त आशंका हो कि ऋणी, उस द्वारा देय धन का संदाय करने  
में असमर्थ है ; या

(घ) यदि किसी अन्य कारण से निगम के हित के संरक्षण के लिए ऐसा करना  
आवश्यक हो।

26. (1) जहाँ निगम को, इस द्वारा दिए गए ऋणों या अग्रिमों अथवा वित्तीय सौकर्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से, जिसके अन्तर्गत ऋणी का प्रतिभू भी है, कोई रकम देय है, वहाँ ऐसी रकम, प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित प्ररूप पर प्रमाण-पत्र दिए जाने पर उस जिले के कलक्टर द्वारा, जिसमें वह व्यक्ति, जिस द्वारा रकम देय है, निवास करता है या कारबार करता है अथवा सम्पत्ति का स्वामी है, भू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूली होगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रयुक्त नहीं होगा ।

(3) ऋण के सम्बन्ध में निगम को देय किसी रकम को वसूल करने के प्रयोजन के लिए उसके प्रतिभू के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व मूल ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा ।

26-क. जहाँ निगम के साथ बंधन प्रबन्ध के अधीन बैंक ने, निगम द्वारा समर्थित आवेदन पर, किसी व्यक्ति को ऋण दिया है, और ऐसा व्यक्ति—

बैंकों के कतिपय देय को भू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूली ।

- (i) ऋण या अग्रिम जिसके अन्तर्गत व्याज भी है अथवा उसको किसी किस्त के प्रति संदाय में व्यतिक्रम करता है ; या
- (ii) ऋण देने की शर्तों या धारा 25 के अधीन दायी होने पर, ऐसे ऋण या उसके किसी भाग के प्रतिदाय या प्रतिमंदाय में व्यतिक्रम करता है ;
- (iii) अन्यथा करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहेगा ; तब बैंक या इसका प्राधिकृत अधिकारी, उसका पदनाम जो भी हो, अनुसूची में दिए गए प्रारूप पर प्रमाण-पत्र, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि वर्णित करके और यह अनुरोध करते हुए कलक्टर को भेज सकेगा कि ऐसी राशि वसूली की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत व्याज के साथ वसूली प्रभार सहित वसूल की जाए मानो यह भू-राजस्व की वकाया हो ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन भेजा गया प्रमाण-पत्र में वर्णित बात का निश्चायक सबूत होगा और ऐसे प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् कलक्टर, इसमें वर्णित रकम को भू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा ।

(3) इस धारा की कोई बात,—

- (क) किसी बंधक, प्रभार, गिरवी या अन्य विल्लंगम द्वारा किसी सम्पत्ति में, राज्य सरकार, बैंकिंग कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के किसी सृजित हित को प्रभावित नहीं करेगी ; या
- (ख) इस अधिनियम या तद्धीन विरचित नियमों के अधीन करार के सम्बन्ध में या इस उप-धारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी हित के बारे में की गई किसी क्षतिपूर्ति, संविदा या प्रतिभूति की बाबत, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद को अपवर्जित या किसी अधिकार अथवा उपाय को प्रभावित नहीं करेगी ।

वसूली प्रभार । 26-ख. धारा 26 (क) के अधीन कलक्टर की सेवाओं का लाभ उठाने वाला बैंक, सरकार को ऐसी दरों पर संग्रहण प्रभार संदत्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ।

ऋणी की सम्पत्ति पर प्रभारों की पूर्विक्ता से सम्बन्धित किसी विधि के उपबंधों और भू-राजस्व या बकाया निगम का निगम का रूप में इस द्वारा वसूलीय किसी धन के सम्बन्ध में बैंक या सरकार के किसी पूर्व दावे के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम की धारा 26 में यथा अवधारित निगम के और धारा 26-क में यथा अवधारित बैंक के देय, उस पर प्रोद्भूत ब्याज और वसूली की लागत सहित ऋणी और प्रतिभू, यदि कोई हो, की सम्पत्ति पर प्रथम भार होंगे ।

#### अध्याय—6

#### लेखा और संपरीक्षा

लेखा । 28. (1) निगम का तुलन-पत्र और लेखें, जिनके अन्तर्गत लाभ और हानि लेखा भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार और रखे जाएंगे, जो विहित की जाए ।

संपरीक्षा । 29. (1) निगम के लेखाओं की संपरीक्षा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उप-धारा (1) के अधीन संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्बन्ध रूप से अहित संपरीक्षकों द्वारा की जाएगी जिनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी और वे निगम से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो बोर्ड द्वारा नियत किया जाए ।

1956 क

(2) संपरीक्षकों को वार्षिक तुलन-पत्र और निगम के लाभ हानि के लेखाओं की एक प्रति दी जाएगी और उनका यह कर्तव्य होगा कि वे उनकी और उसके साथ ही उन से संबंधित लेखाओं और बाउचरों की जांच करे और वे निगम द्वारा रखी गई सभी बहियों की सूची प्राप्त करेंगे और उनको निगम की बहियां, लेखे और अन्य दस्तावेज सभी उचित समयों पर प्राप्य होंगे । वे निगम के किसी निदेशक या अधिकारी से ऐसी सूचना की अपेक्षा कर सकेंगे जैसी कि संपरीक्षक अपने संपरीक्षक के रूप में कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(3) संपरीक्षक अपने द्वारा परीक्षित वार्षिक तुलन-पत्र और लेखाओं पर रिपोर्ट निगम को देंगे और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वे यह कथन करेंगे कि क्या उनकी राय में तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन पत्र है जिस में सभी आवश्यक विशिष्टियां हैं और यह उचित रूप से लिखा गया है जिससे निगम के कार्यकलापों की स्थिति का सच्चा और सही रूप प्रदर्शित होता है ।

(4) निगम सरकार को अपने तुलन पत्र और लेखाओं की प्रति और साथ ही संपरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति और सुसंगत वर्ष के दौरान निगम के कार्यकरण की रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं के बन्द और संतुलित किए जाने की तारीख से चार मास के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(5) पूर्वगामी उप-धाराओं की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम के लेखाओं की संपरीक्षा, जब कभी भी लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और

समीचीन हो, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अभिकरण द्वारा भी की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा और रिपोर्ट के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय अभिकरण को निगम द्वारा संदेय होगा ।

29-क. राज्य सरकार धारा 29 की उप-धारा (4) के अधीन इसे निगम द्वारा निगम के कार्यकरण के बारे में वार्षिक और संपरीक्षा रिपोर्ट पेश किए जाने के पश्चात् यथा-शक्य शीघ्र, किन्तु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से संज्ञित सौ मास की अवधि के भीतर, जिससे ऐसी रिपोर्ट संबंधित है, उक्त वार्षिक और संपरीक्षा रिपोर्ट को, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना ।

### अध्याय—7

#### प्रकीर्ण

30. (1) कम्पनियों या निगमों के बन्द किए जाने, विघटन या समापन से सम्बन्धित इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के उपबन्ध निगम को लागू नहीं होंगे ।

बोर्ड का विघटन ।

(2) राज्य सरकार, यदि निगम अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करता है, या धारा 29 के अधीन रिपोर्ट मिलने पर निगम से यह कारण बताने की अपेक्षा करती है कि उसे क्यों विघटित न किया जाए, और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है या यदि स्पष्टीकरण राज्य सरकार के समाधान प्रद रूप में नहीं है तो वह ऐसी तारीख से जो निश्चित की जाए बोर्ड को विघटित कर सकेगी ।

31. (1) जब धारा 30 के अधीन बोर्ड का विघटन किया जाता है तो—

बोर्ड के विघटन के परिणाम ।

(i) सभी निदेशक विघटन की तारीख से अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ii) विघटन की अवधि के दौरान बोर्ड की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाएं;

(iii) निगम में निहित सभी निधियां और अन्य सम्पत्ति विघटन की अवधि के दौरान राज्य सरकार में निहित होंगी ।

(2) सरकार, स्थाविवेकानुसार, ऐसी अवधि के पश्चात् निगम का पुनर्गठन कर सकेगी जैसा वह उचित समझे ।

32. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी सिविल न्यायालय को किसी मामले के सम्बन्ध में कोई बाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए निगम या इस अधिनियम के अधीन अथवा इस द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई न्यादेश नहीं दिया जाएगा ।

अधिकारिता का वर्जन ।

सद्भावपूर्वक  
की गई  
कार्रवाई के  
लिए संरक्षण।

33. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या हो सकने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए कोई भी बाद या अन्य विधिक कार्यवाही, निगम या निदेशक जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक या निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राविष्ट कोई अधिकारी या कर्मचारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति भी है, के विरुद्ध नहीं होगी।

कर्मचारियों  
का लोक  
सेवक होना।

34. प्रबन्ध निदेशक और निगम के अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

निदेशकों की  
क्षतिपूर्ति।

35. (1) प्रत्येक निदेशक की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा उपगत सभी हानियों और व्ययों की बाबत, जो उसके जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम से न हुए हों, निगम द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

(2) कोई निदेशक निगम के किसी अन्य निदेशक के लिए या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या निगम की किसी ऐसी हानि या व्यय के लिए जो निगम की ओर से सद्भावपूर्वक अर्जित या ली गई किसी सम्पत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या उसमें हक की अपर्याप्तता या कमी के अधीन अथवा अपने पद के या उससे सम्बन्धित कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के फलस्वरूप हो, उत्तरदायी नहीं होगा।

रजिस्ट्रीकरण  
फीस और  
स्टाम्प शुल्क  
से छूट।

36. निगम द्वारा या उसकी ओर से इसके कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में निष्पादित सभी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से छूट होगी ;

परन्तु स्टाम्प शुल्क के संदाय से छूट केवल ऐसी लिखतों के मामले में लागू होगी जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क में विनिर्दिष्ट है।

1899 का 2

विनियम  
बनाने की  
शक्ति।

37. (1) धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों के अधीन रहते हुये, बोर्ड ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है, उपबन्ध कराने के लिए ऐसे विनियम बना सकते हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

- (क) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत कारबार में संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है ;
- (ख) निगम द्वारा ऋण देने या अन्य प्रबन्ध करते समय अधिरोपित की जाने वाली शर्तें ;
- (ग) ऋणों पर व्याज की दर ;
- (घ) कर्तव्य, जिनका प्रबन्ध निदेशक द्वारा पालन किया जाएगा ;
- (ङ) निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य, आचरण, वेतन, भत्ते और भेवा की शर्तें ;



- (च) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्या-योजन;
- (छ) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भविष्य और अन्य लाभकारी निधियों की स्थापना और रखा जाना ;
- (ज) सामान्यतः निगम के क्रियाकलापों का कुशल संचालन ;
- (झ) विनियमों द्वारा विहित किए जाने के लिए, अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुशात सभा विषय ।

38. (1) सरकार इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात :

- (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य निदेशकों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उन्हें संदेय फीस और भत्ते;
- (ख) प्ररूप जिसमें प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा;
- (ग) प्ररूप और रीति जिसमें लेखे रखे जायेंगे और तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लखा तैयार किया जाएगा ; और
- (घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा हो या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

39. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

## “अनुसूची

[धारा 2 (टट) और धारा 26-क देखें]

कार्यालय प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक ।

प्रमाणित किया जाता है—

(1) कि श्री/श्रीमती-----निवासी-----तहसील-----  
-----जिला-----को-----रुपये की  
राशि-----के लिए मंजूर की गई है ;

(2) कि उक्त ऋणी से-----दर से प्रभार्य ब्याज के रूप में  
-----रुपये की और राशि वसूलीय हो गई है ;

(3) कि उक्त श्री/श्रीमती-----ने उससे वसूलीय मूल या  
ब्याज का प्रतिदाय नहीं किया है और ऐसा करने के लिए अनिच्छुक है ;  
और

(4) कि उससे-----रुपये की कुल राशि(-----  
-----रुपये मूल के रूप में और -----रुपये  
ब्याज के रूप में) वसूलीय हो गई है ;

अतः अब यह अनुरोध किया जाता है कि-----रुपये की  
कथित राशि (-----रुपये) वसूली प्रभारों के हिमाचल प्रदेश  
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 की  
धारा 26-क के अर्जित भू-राजस्व की बकाया के रूप में, वसूल की जाए ।

प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक,  
-----बैंक ।

सेवा में,

कलक्टर

-----जिला----- ।”